

# देश की उपासना

(देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए)

वर्ष - 02

अंक - 312

जैनपुर, गुरुवार, 08 अगस्त 2024

सान्ध्य दैनिक (संस्करण)

पेज - 4

मूल्य - 2 रुपये

## संक्षिप्त खबरें

### प्रदेश में एक अक्तूबर से होगी धान रवाई

लखनऊ, संवाददाता। प्रदेश सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत एक अक्तूबर से पश्चिमी यूपी और एक नवंबर से पूर्वी यूपी के जिलों में किसानों से सीधे धान की खरीद शुरू करने के निर्देश दिए हैं। खाद्य एवं रसद विभाग ने इस संबंध में समय सारियों जारी की है। प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद आलोक कुमार ने बताया कि ई-टेंडर के माध्यम से हैंडलिंग ठेकेदारों की नियुक्ति, परिवहन के लिए ठेकेदारों की नियुक्ति पश्चिमी यूपी के जिलों में 25 अगस्त और पूर्वी यूपी के जिलों में 31 अगस्त तक कर ली जाएगी।

### कांग्रेस देश को अराजकता की स्थिति में धकेलना चाहती - अनुराग

नई दिल्ली, एजेंसी। विषय के नेता राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से वायनाड भूखलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि वायनाड में भीषण त्रासदी हुई है। वे कुछ दिन पहले अपनी बहन के साथ वायनाड गए थे और इस त्रासदी से उत्पन्न तबाही, दर्द और पीड़ा को उन्होंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से धकेलना चाहती है।

### कोई राज्य पश्चिम बंगाल का मॉडल नहीं अपनाना चाहेगा - शाह



कोई समस्या नहीं है जिन्होंने अच्छा प्रश्नें किया है, लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी राज्य पश्चिम बंगाल मॉडल को लागू करना पसंद नहीं करेगा। वहीं, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में 53 प्रतिशत की कमी आई है तथा इन घटनाओं में सुरक्षा बलों की मात्रा के मामलों में भी 72 प्रतिशत की कमी हुई है। उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद की गतिविधियों में लिप्त लोग इस देश के संविधान और लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं तथा वे हथियार के माध्यम से सत्ता हथियाना चाहते हैं। राय ने कहा कि वर्ष 2010 में 96 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे।

कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार

### वायनाड भूखलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे केंद्र सरकार - राहुल



राहुल गांधी ने वायनाड का विश्लेषण किया

उन्होंने कहा, वहां पर पहाड़ का लगभग दो किलोमीटर का हिस्सा पूरा गिर गया है। सैकड़ों लोग मारे गए हैं, और कई लापता हैं। हालांकि अंततः हताहों की संख्या चार सौ से अधिक होने की आशंका है। उन्होंने

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने वायनाड के भीषण त्रासदी के बातों को लोकसभा में धकेला

राहुल गांधी ने व

# संपादकीय बजट में वृद्धि

केंद्रीय बजट में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो यह आवंटन ऐसे देश के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है, जिसने कार्यबल में महिलाओं की बेहद कम भागीदारी देखी है। विश्व आर्थिक मंच के 2024 के वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में भारत 146 देशों में 129वें स्थान पर है। नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) ने बताया कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी दर 2022–23 में 35.9 प्रतिशत थी, जबकि पुरुषों की 76 प्रतिशत थी – 40 प्रतिशत से अधिक का अंतर। हालांकि 2017–18 के पीएलएफएस दौर से महिलाओं की भागीदारी में 13.9 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई है, लेकिन इसका श्रेय ज्यादातर स्वरोजगार को जाता है, जो लगभग 65 प्रतिशत है। स्वरोजगार में महिलाओं की एकाग्रता, ज्यादातर अनौपचारिक, नीतिगत दृष्टिकोण से एक बड़ी चिंता बनी हुई है क्योंकि यह निम्न—गुणवत्ता वाले काम और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंचने में चुनौतियों को दर्शाता है। रोजगार सृजन और रोजगार क्षमता में सुधार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की गई हैं। पीएलएफएस ने दिखाया है कि महिलाएँ ज्यादातर सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों में कार्यरत हैं। नवीनतम बजट का उद्देश्य उद्योग के सहयोग से छात्रावासों की स्थापना और क्रेच की स्थापना के माध्यम से कामकाजी महिलाओं का समर्थन करना है, जो महिलाओं की विभिन्न क्षेत्रों में काम करने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। महिलाओं की कार्य भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ अन्य प्रस्तावों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच शामिल है। ऐसी पहलों में उद्यमिता को बढ़ावा देने की क्षमता है। छोटे उद्यमों और विनिर्माण, विशेष रूप से श्रम—गहन विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाना एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र महिलाओं के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। बजट में एक पैकेज शामिल है जिसमें विकास को प्रोत्साहित करने के लिए छोटे उद्यमों के लिए वित्तपोषण, विनियामक परिवर्तन और प्रौद्योगिकी सहायता शामिल है। हालांकि विनिर्माण शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार देने वाले सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है, लेकिन वे ज्यादातर परिधान, कपड़ा और तम्बाकू क्षेत्रों में निम्न—स्तरीय प्रसंस्करण कार्यों में कार्यरत हैं। जुलाई 2020 में उद्यम पंजीकरण पोर्टल की स्थापना के बाद से इस पर पंजीकृत कुल एमएसएमई में महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई की हिस्सेदारी 20.5 प्रतिशत है। उद्यम—पंजीकृत एमएसएमई के कुल कारोबार में महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई का योगदान 10.22 प्रतिशत है। हालांकि, एमएसएमई में वेतन अंतर है क्योंकि महिलाएँ ज्यादातर अनौपचारिक व्यवस्था में हैं। शैक्षिक योग्यता, कौशल, पर्याप्त कल्याण की कमी, साथ ही घरेलू देखभाल की जिम्मेदारियों का बोझ महिलाओं को इन क्षेत्रों की ओर धकेलता है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, सरकार ने अतीत में कई योजनाएँ शुरू की हैं, जिनमें महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित सखी निवास के रूप में जानी जाने वाली कामकाजी महिलाओं के छात्रावास शामिल हैं। इस केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य शहरी, अर्ध—शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए उनके बच्चों के लिए डेकेयर सुविधाओं के साथ सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है। वर्तमान में, देश में बच्चों की डेकेयर सुविधाओं के साथ 494 केंद्र प्रायोजित कार्यात्मक कामकाजी महिला छात्रावास हैं। 1972–73 में शुरू की गई यह योजना 2021–22 में सामर्थ्य उप—योजना के तहत मिशन शक्ति का हिस्सा बन गई। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान इस योजना के लिए बजट आवंटन 87.40 करोड़ रुपये था। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों ने अभी तक ऐसे छात्रावास स्थापित नहीं किए हैं, जबकि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे कुछ दक्षिणी राज्यों में ऐसे छात्रावासों की संख्या अद्याके है। नए बजट आवंटन वाले राज्यों में इन्हें मजबूत किया जा सकता है, जहाँ कम या कोई छात्रावास नहीं हैं। जनवरी 2024 में, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने नियोक्ताओं के लिए एक सलाह जारी की, जिसमें कामकाजी महिलाओं के लिए केंद्र बनाने की आवश्यकता को दर्शाया गया, जहाँ स्थानीय बड़े और छोटे उद्यम संलग्न क्रेच और वरिष्ठ देखभाल सुविधाओं के साथ सामान्य सुविधाएँ बनाने के लिए सहयोग कर सकते हैं। छोटे उद्यमों के लिए बजटीय सहायता का उपयोग ऐसे केंद्र बनाने के लिए किया जा सकता है, जिससे महिलाओं के लिए कार्यबल में शामिल होना संभव हो सके। कौशल पर बजट का जोर ढेर सारे अवसरों को खोलता है। एक दिलचस्प पहलू यह है कि इसका ध्यान कौशल पाठ्यक्रमों पर है जो लंबे समय से अकादमिक और नीतिगत चर्चा में रहे हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) पर महिलाओं के लिए ब्यूटीशियन और टेलरिंग पाठ्यक्रम और पुरुषों के लिए ड्राइविंग, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल पाठ्यक्रम जैसे लैंगिक रुद्धिवादी ट्रेडों को बढ़ावा देने के लिए सवाल उठाए गए हैं। पीएलएफएस के अनुसार, 2021–22 में 15–59 आयु वर्ग में 12.3 प्रतिशत महिलाओं और 26 प्रतिशत पुरुषों ने व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसमें स्पष्ट लिंग अंतर है।

# विभाजनकारी साजनीति से दूर रहें

ललित  
गीतार्थ पाठक द्वारा शायद भारत के वर्तमान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा किसी अन्य राजनेता में शब्दों को इतनी तेजी से जोड़ने की चतुराई नहीं है कि वह जो कुछ भी कहते हैं उसका विपरीत अर्थ दे सकें। उनकी इस टिप्पणी के बाद कि विपक्षी कांग्रेस महिलाओं के मंगलसूत्र सहित भारतीयों की संपत्ति छीनने और इसे घुसपैठियों को देने की योजना बना रही है, जिनके अद्याक बच्चे हैं, जिससे विवाद पैदा हो गया और विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री की आलोचना की। इसके अर्थ में मोड़ दे दिया। एक साक्षात्कार में कहा, मुझे चिंता है कि अधिक बच्चों वाले लोगों के बारे में टिप्पणी केवल मुसलमानों से कैसे जुड़ी है! वे मुसलमानों के साथ ऐसा व्यवहार कराएं कुछ तो है।

जो जना बना रही थी। राजनीतिक विचारकों और विश्लेषकों ने सोचा कि लोकसभा चुनावों में झटका लगने के बाद सत्तारूढ़ दल अपनी इस्लाम विरोधी बयानबाजी कम कर देगा। यालैंकि, यह एक भ्रम था क्योंकि ये नेता अब भी इस्लाम विरोधी विषय पर फिर से विचार करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और मध्य देश सरकार के हालिया निर्देशों में आंतिपूर्ण और व्यवरित तीर्थात्रा मुनिश्चित करने के लिए कांवर यात्रा गार्ग पर भोजनालयों को मालिकों के नाम और पहचान प्रदर्शित करना मनिवार्य है, जो भाजपा के निरंतर अल्पसंख्यक विरोधी रुख का एक और उदाहरण है। सौभाग्य से, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में निर्देशों पर रोक लगा दी। केंद्रीय कृषक अधिकारी ने एक पार्टी बैठक में सत्तारूढ़ भाजपा के अल्पसंख्यक सेल को खत्म करने और घटक का साथ के नारे को उखाड़ फेंकने का आवान किया। सबका विकास। सरकार अपने आंकड़ों के अनुसार, भारत व सभी प्रमुख धार्मिक समूहों के बीच मिलिम एन्डरन ट्रॉप में स्पष्टपे त्रै

गिरावट देखी जा रही है मोदी के भरोसेमंद मुख्यमंत्रियों में से एक, असम के हिमंत बिस्था सरमा और झारखंड में आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के सह-प्रभारी ने हाल ही में झारखंड में कहा कि संथाल परगना के आदिवासी बहुल क्षेत्र की पूरी जनसांख्यिकी तेजी से बदल रही है। वहां अनियंत्रित बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए इलव जिहादश और श्लैड जिहादश तक। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेशी मुसलमान उनकी जमीन और पैतृक संपत्ति हड्डपने के लिए आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं। उन्होंने रांची में यह भी कहा कि असम में मुस्लिम आबादी आज 40 फीसदी तक पहुंच गयी है। उनके अनुसार 1951 में यह 12 प्रतिशत थी। उन्होंने कहा कि असम के कई जिले मध्यस्थानों के द्वारा ऐसे चिकन्हा गां

A black and white illustration depicting a political rally or speech. A man in a dark suit and tie stands on a raised platform, facing a large crowd of people. He has his right arm raised, gesturing as if speaking. The crowd is shown from behind, appearing as a dense assembly of people. The scene is set outdoors under a clear sky.

An illustration depicting a political rally or assembly. In the foreground, the back of several audience members' heads are visible, looking towards a stage. On the stage, a speaker is standing behind a podium, gesturing with their right hand while speaking. The background is filled with a dense crowd of people, all appearing to be wearing white or light-colored clothing, possibly traditional attire. The overall atmosphere suggests a formal or organized event.



